बैड लोन पर पूर्व गर्वनर का पत्र

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

13 सितम्बर, 2018

*''हाल ही में संसद की प्राक्कलन समिति को भेजे पत्र में आरबीआई के पूर्व गर्वनर रघुराम राजन ने उन तरीकों के बारे में बताया है जिनके जरिये बेईमान बिजनेस घरानों को सरकार और बैंकिंग व्यवस्था से घोटाला करने की खुली छूट मिली थी।'' इस कथन के संदर्भ में अंग्रेजी समाचार पत्र **'द हिन्दू' और 'इंडियन एक्सप्रेस'** में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे **GS World** टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।*

एक आदर्श सलाह: रघुराम राजन के सुझावों पर (द हिन्दू)

''वित्तीय संकट को रोकने के लिए रघुराम राजन द्वारा दिए गये सुझावों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।''

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अगले वित्तीय संकट पर सावधानी बरतने के लिए सभी को आगाह किया है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। बैंकों के गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) पर संसद की प्राक्कलन समिति को लिखे अपने नोट में, श्री राजन ने संभावित समस्याओं के तीन प्रमुख कारणों को बताया है: मुद्रा क्रेडिट, जो मूल रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रदान किए जाते हैं; किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को उधार देना; और लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा संचालित एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत आकस्मिक देनदारियां।

अकेले मुद्रा ऋण के तहत ₹ 6.37 लाख करोड़ वितरण किए गये हैं, जो कुल बकाया बैंक क्रेडिट का 7% से अधिक है। इन ऋणों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य 'अनफंडेड को फंड प्रदान करना है', एनडीए सरकार की मुख्य योजना है।

यह देखते हुए कि उधारकर्ता अधिकतर अनौपचारिक क्षेत्र से है और उन्हें 10 लाख तक के छोटे ऋण दिए जा रहे हैं, बैंकों को इनकी जांच बारीकी से करनी चाहिए थी। हांलाकि, यहाँ एक सवाल यह है वर्तमान में क्या बैंकों के पास व्यवसाय करने वाले बड़े उधारकर्ताओं से वसूली करने के लिए संसाधन और मैनपावर मौजूद है?

इसका जवाब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये छोटे-छोटे ऋण धारक ही आगे चल कर एक बड़े क्रेडिट मुद्दे का निर्माण करेंगे। इसका ही एक उदाहरण किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए गये ऋण है, जिसका भुगतान बाद में सरकार को ही करना पड़ रहा है।

ऋण छूट पर श्री राजन की सलाह अतीत में उनके और दूसरों द्वारा दी जाती रही है। लेकिन राजनीतिक वर्ग ने इस सलाह पर कभी भी ध्यान देना उचित नहीं समझा, हमेशा क्रेडिट संस्कृति को खराब करने और नैतिक खतरे का निर्माण करने जैसे नीतियों का चयन किया है जहां किसान-उधारकर्ता को यह विश्वास हो चुका है कि उनके द्वारा लिया गया ऋण सरकार ही चुकाएगी।

नोट फ्रॉम राजन (इंडियन एक्सप्रेस)

''आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने बैड लोन समस्या से निपटने के उपायों में कई कमियों को इंगित किया हैं। सरकार को उसे सुनना चाहिए।''

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा संसद की प्राक्कलन समिति को प्रस्तुत नोट व्यापक रूप से यह दर्शाता है कि भारत की बैंकिंग प्रणाली में क्या गलत है और यह समस्या क्यों अभी तक जारी है। श्री राजन ने बैंकों में शासन और बैड लोन में धोखाधड़ी से लेकर कई मुद्दों को फिर से ध्वजांकित किया है।

इस मोर्चे पर प्रगति की कमी को देखते हुए, राजन चाहते हैं कि इस मुद्दे को तत्काल संबोधित किया जाए, विशेष रूप से उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को उच्च प्रोफाइल धोखाधड़ी के मामलों की एक सूची प्रस्तुत की है, ताकि उस पर समन्वित कार्रवाई कीया जा सके।

पश्चिम के विपरीत, जब आर्थिक अपराधियों को दंडित करने की बात आती है तो भारत का ट्रैक रिकॉर्ड - जो लोग भारतीय बाजारों या पूंजी बाजारों में निवेशकों को धोखा देते हैं, काफी खराब हैं।

यह लगातार सरकारों द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने के कारण हो रहा है, क्योंकि यहाँ जांच वर्षों तक खींचती हैं और न्यायिक प्रणाली में भी देरी हैं।

असल में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकरों के लिए अयोग्य उधारकर्ताओं के लिए अपने दरवाजे खोलने के लिए किसी राजनीतिक झुकाव या दबाव की भी जरूरत नहीं थी। वे वैसे भी इस काम के लिए तैयार थे। जैसा कि राजन ने कहा है कि उच्च आर्थिक विकास वाले चरण ने छुपे हुए भविष्य जोखिमों के बारे में अधिकतर बैंकरों को अन्धा बना दिया था। उन्होंने लोन देते वक्त केवल कंपनियों के पिछले प्रदर्शन को देखा और भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन की ही उम्मीद रखी।

उन्होंने उम्मीद की कि दो अंकों वाला आर्थिक विकास जारी रहने वाला है और ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त कैश फ्लो बना रहेगा। कई मामलों में, अधिकांश बैंकरों ने लोन स्वीकृत करते समय केवल नामों को देखा. जैसे, विजय माल्या एक बड़ा उदाहरण है।

आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने एनपीए पर आरबीआई की नीतियों पर हो रहे विरोध का हमेशा बचाव किया है। इस दौर में समुचित दिवालिया संहिता (बैंकरप्सी कोड) नहीं होने की स्थिति ने बैंकों के लिए कर्जदारों पर जुर्माना लगाकर कर्जों को बट्टे खाते में डालने (राइट ऑफ करने) को मुश्किल बना दिया; इसका नतीजा खराब कर्जों को जिलाए रखने के तौर पर निकला।

हालांकि राजन ने गलत आचरण और धोखाधड़ी को भी इसकी वजहों के तौर पर गिनाया और कहा कि कार्रवाई करने को लेकर व्यवस्था की अनिच्छा भी एक गंभीर समस्या है। केंद्र सरकार को अच्छे दिखने वाले वक्तव्यों पर भी ध्यान देना चाहिए।

वर्तमान गड़बड़ी के पुनरावृत्ति को रोकने के अपने सुझावों में से एक है, एक स्वतंत्र बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा की गई नियुक्तियों के साथ बैंक बोर्डों को प्रोफेशनल बनाना होगा; बाहरी बैंकों से घाटे के निपटारे के लिए नए प्रतिभाओं को शामिल करना होगा।

यह हमारी बदनसीबी है कि हमारे राजनेता श्री राजन द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के बजाए उन बिंदुओं का चयन किया जो उनके लिए सुविधाजनक हैं अर्थात उस अवधि के बारे में बात करना जब बैड लोन का निर्माण होना शुरू हुआ।

* * *

श्री राजन के अनुसार, विशिष्ट ऋण के लिए जिम्मेदार बैंकरों को पकड़ने के बजाय, बैंक बोर्ड और जांच एजेंसियों को बैड लोन के लिए जिम्मेदार सीईओ की तलाश करनी चाहिए।

दरअसल, बैंकरों को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए जब तक उनके द्वारा लिए गये निर्णय सही नहीं साबित हो जाते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि अगर कुछ शीर्ष निजी उधारदाताओं समेत बैंकों के कई बोर्डों द्वारा बेहतर शासन प्रणाली स्थापित की जाती है, तो बैड लोन का स्तर बहुत कम हो जाएगा।

राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों में बैड लोन के मुद्दे को पहचानने में धीमी गति से चलने के बाद, सरकार ने इन बैंकों में से कई में खराब शासन प्रणाली की समस्या को संबोधित नहीं किया है।

अपने क्रेडिट के लिए, सरकार और नियामक ने दिवाला और दिवालियापन पर कानून के अधिनियमन के साथ क्रेडिट संस्कृति में बदलाव लाने का प्रयास किया है।

* * *

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में संसद की प्राक्कलन समिति को भेजे पत्र में आरबीआई के पूर्व गर्वनर रघुराम राजन ने उन तरीकों के बारे में बताया है जिनके जरिये बेईमान बिजनेस घरानों को सरकार और बैंकिंग व्यवस्था से घोटाला करने की खुली छूट मिली थी।
- साथ ही उन्होंने कहा कि अधिक आशावादी बैंकरों, सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में धीमी गति और आर्थिक विकास में सुधार ने मुख्य रूप से बढ़ते बैड लोन में योगदान दिया है।
- रघुराम राजन ने आगे कहा कि अधिक बैड लोन साल 2006-2008 के बीच में दिया गया, जब आर्थिक विकास काफी मजबूत था और पूर्व में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे पावर प्लांट्स आदि समय पर और बजट के अंदर ही पूरे हो चुके थे।

बैड बैंक

- बैड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं को एक नए बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये बैड बैंक कर्ज में फँसी बैंकों की राशि को खरीद लेगा और उससे निपटने का काम भी इसी बैंक का होगा।
- जब किसी बैंक की गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ सीमा से अधिक हो जाती हैं, तब राज्य के आश्वासन पर एक ऐसे बैंक का निर्माण किया जाता है जो मुख्य बैंक की देयताओं को एक निश्चित समय के लिये धारण कर लेता है।

स्वागत योग्य क्यों?

- बैड बैंक की चर्चा केंद्र में इसलिये है, क्योंकि इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में बैड बैंक का जिक्र किया गया है। हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगढ़िया ने भी डूबते कर्ज से निपटने के लिये बैड बैंक को बेहद जरूरी बताया है।
- बैड बैंक एआरसी यानी परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों की तरह काम करेगा। बैड बैंक, एक ऐसा बैंक होगा जो दूसरे बैंकों के डूबते कर्ज को खरीदेगा।
- बैड बैंक का नाम 'पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी' यानी पीएआरए होगा और यह प्रयोग जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस जैसे देशों में सफल रहा है।

संबंधित समस्याएँ

- बैड बैंक की स्थापना में सबसे बड़ी समस्या बैंक में हिस्सेदारी को लेकर है। यह जानना दिलचस्प है कि समस्या निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों के अधिकतम भागीदारी से है।

- यदि बैड बैंक में सरकार की हिस्सेदारी अधिक हो तो बैंकों की गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ इतनी अधिक हो गई है कि बैड बैंक के माध्यम से इनकी खरीद पर सरकार को उल्लेखनीय व्यय करना पड़ सकता है।
- साथ ही एक सरकारी बैड बैंक को उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जिनका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के सन्दर्भ में कर रहे हैं।
- यदि बैड बैंक को निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया गया तो सबसे बड़ी समस्या गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के मूल्य को लेकर हो सकती है।
- निजी क्षेत्र का बैड बैंक अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों का मूल्य तय करेगा। यदि यह मूल्य बहुत अधिक हुआ तो बैड बैंक का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा और यदि यह मूल्य बहुत ही कम हो गया तो बैंकों को उनकी ऋण देयता के अनुपात में राशि नहीं मिल पाएगी।

दोहरे तुलनपत्र की चुनौती

- दोहरे तुलनपत्र की चुनौती सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों और कुछ बृहत् कॉर्पोरेट घरानों की अनर्जक वित्तीय स्थितियां हैं।
- बैंकिंग व्यवस्था की समस्याएं कुछ दिनों से बढ़ रही हैं। प्रतिबलित आस्तियां (अनर्जक ऋण पुनर्गठन और आस्तियों) में पिछले कुछ वर्षों से वृद्धि हो रही हैं जिसका प्रभाव पूंजीगत परिस्थितियों पर पड़ा हैं। बैंकों ने पूंजी संरक्षण के उद्देश्य से बाजार में ऋण के प्रवाह को सीमित किया हैं।
- कुछ मामलों में तुलनपत्र की ये सुभेद्यता कॉर्पोरेट क्षेत्र में देखे गए हैं, विशेष रूप से अवसंरचना और वस्तु संबंधी व्यवसायों में जैसे इस्पात में निवेश करने हेतु ऋण लिए लेकिन बाजार की कमजोरियों की वजह से वो ऋण लौटा नहीं पाए।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. पूर्व गर्वनर रघुराम राजन ने एनपीए (गैर निष्पादित संपत्ति) की समस्या के लिए किन्हें जिम्मेदार माना है?

1. मुद्रा ऋण
2. किसान क्रेडिट कार्ड योजना
3. लघु उद्योग हेतु एमएसएमई ऋण
4. आवास योजना ऋण

नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करें-

(a) 1, 2 और 4
(b) 1, 3 और 4
(c) 1, 2 और 3
(d) उपरोक्त सभी

2. निम्न में से कौन-सा/से कदम एनपीए की समस्या को हल करने में मद्दगार होंगे?

1. बैंक बोर्ड ब्यूरों की नियुक्ति
2. पेशेवर लोगों की नियुक्ति
3. दिवालिया संहिता का क्रियान्वयन

नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करें-

(a) 1 और 2
(b) 1 और 3
(c) 2 और 3
(d) उपरोक्त सभी

3. निम्नलिखित में किन-किन कारकों ने एनपीए की समस्या को बढ़ाया?

1. बैंकों द्वारा जोखिमों को नजरअंदाज करना
2. लोन का निर्धारण कंपनी के पिछले प्रदर्शन से किया जाना
3. बड़े घरानों के केवल नाम पर ऋण

नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करें-

(a) 1 और 2
(b) 2 और 3
(c) 1 और 3
(d) उपरोक्त सभी

नोट :
12 सितम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. बैंकों पर एनपीए के मंडराते संकट के मध्य अभी भी बैंकिंग क्रेडिट संबंधी नीति पर सावधानी नहीं बरती जा रही है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Despite looming NPA problem on Banks, now also precaution is not being taken on the policies related to banking credit. To what extent you agree with this statement. (250 Words)